

उभरता भारत: स्थिरता और अवसरों की भूमि*

शक्तिकान्त दास

मुझे भारतीय आर्थिक अध्ययन संस्थान (आईआईईएस), टोक्यो द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर आयोजित इस संगोष्ठी में भाग लेने में प्रसन्नता हो रही है। मुझे जानकारी मिली है कि कोविड-19 महामारी के बीच की अवधि के कारण तीन वर्षों के अंतराल के बाद आईआईईएस द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में, मार्च 2023 में, प्रोफेसर सकाकीबारा और श्री सुगया ने मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का दौरा किया था और उस समय हमने इस संगोष्ठी में मेरी सहभागिता के बारे में चर्चा की थी। आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं प्रोफेसर सकाकीबारा और आईआईईएस को अपना हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई व्यापक आर्थिक और भू-राजनीतिक आघातों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक मंदी की भविष्यवाणी सच नहीं हुई है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि सख्त वित्तीय स्थितियों और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति के बीच वैश्विक संवृद्धि धीमी हो रही है। इधर महामारी, यूक्रेन युद्ध और मौद्रिक नीति की अभी तक की सर्वाधिक सख्ती के दुष्परिणाम से दुनिया प्रभावित है, उसी समय पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों की फेहरिस्त को बढ़ा दिया है। इस परिदृश्य में संवृद्धि बनाम मुद्रास्फीति; मूल्य स्थिरता बनाम वित्तीय स्थिरता; और वर्तमान आपात स्थिति बनाम भविष्य की स्थिरता के बीच तालमेल स्थापित करते हुए नीति निर्माण कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में बहुत सीमित कदम उठाना या बहुत अधिक कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे परिदृश्य में, मैं इस अस्थिर अवधि के दौरान नीति निर्माण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण के साथ शुरू करना चाहूंगा।

* 9 नवंबर 2023 - टोक्यो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, टोक्यो, जापान में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक स्टडीज द्वारा आयोजित सिंपोजियम ऑन इंडियन इकॉनॉमी 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा दिया गया मुख्य भाषण।

हमारा दृष्टिकोण

हाल की अवधि में लगातार हुए आघातों से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमारा प्रयास अपनी नीतिगत प्रतिक्रिया में सक्रिय, व्यावहारिक और विवेकपूर्ण बने रहने का रहा है। हम इस तथ्य से अवगत थे कि संकट स्थिति में अल्पावधि राहत देने के लिए अत्यधिक मौद्रिक हस्तक्षेप करने से भविष्य में कमजोर और नाजुक स्थिति पैदा हो सकती है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद हमने चलनिधि में वृद्धि की, लेकिन चलनिधि वृद्धि का लगभग हर उपाय सीमित अवधि के लिए था और लक्षित था। ऐसा करके, हम चलनिधि कमी के संकट से बच गए। इसके अलावा, हमारे ऋण मानकों को हमारे प्रतिपक्षों (बैंकों) और दबावग्रस्त संस्थाओं या क्षेत्रों को ऋण देने के लिए संपार्श्विक संबंधी आवश्यकताओं को शिथिल नहीं किया गया था।

विनियामकीय पक्ष पर भी हमारे उपाय सावधानीपूर्वक थे। हमने ऋणदाताओं को ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान पर स्थगन की पेशकश करने की अनुमति दी। इसके बाद हमने कोविड-19 से संबंधित दबावग्रस्त आस्तियों के लिए ऋण समाधान ढांचा तैयार किया। यह ऋण समाधान ढांचा मुक्त नहीं था, बल्कि कुछ वित्तीय और परिचालनिक मापदंडों की पूर्ति के अधीन था। ऐसा 'नैतिक खतरे' और अन्य नुकसानों से बचने के लिए किया गया था जो आमतौर पर ऋणों के मुक्त पुनर्गठन से जुड़े होते हैं।

हम इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि स्वस्थ और कुशल बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली विभिन्न आघातों का सामना करने के लिए एक प्राथमिक स्थिरता बल होती है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने अपने विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे में क्रमिक सुधार किए। हमने बैंकों के लिए अभिशासन संबंधी कुछ मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए उनके कारोबार के आकार और जटिलता के आधार पर स्केल आधारित विनियमन शुरू किया है। बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया को भी काफी मजबूत किया गया है, जिसमें कमजोरियों के लक्षणों पर प्रति कार्रवाई

करने के बजाय शीघ्र पहचान और पूर्व-निर्धारित सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

काफी हद तक रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदमों तथा कई कारकों के संयुक्त परिणामों के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिरता और अवसर के प्रतीक के रूप में उभरी है। हमने न केवल बड़े और अतिव्यापी वैश्विक आघातों का सामना करने के लिए अपने आपको तैयार रखा है, बल्कि हमने अपने समष्टिआर्थिक आधार और बफर में भी सुधार किया है। संवृद्धि अपनी पटरी पर बनी हुई है, और मुद्रास्फीति नरमी के रास्ते पर है, लेकिन अभी भी लक्ष्य से ऊपर है। बैंकों और कंपनियों के तुलनपत्र लंबे समय के बाद सर्वाधिक स्वस्थ स्थिति में हैं और सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के चलते वे निवेश में निरंतर पुनरुद्धार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहे हैं। उपभोक्ता विश्वास, जैसा कि हमारे सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता है, महामारी के निचले स्तर के बाद से बढ़ रहा है। हमारा बाहरी क्षेत्र विश्वास को प्रेरित करता है क्योंकि हम सेवा क्षेत्र में निर्यात के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं; हमारा चालू खाता घाटा पूरी तरह से नियंत्रणाधीन है; और हमने संभावित घटनाओं से निपटने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया है।

आज भारत अपनी युवा जनसांख्यिकी¹, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार और सक्षम नीतिगत वातावरण, जोकि सबसे महत्वपूर्ण है, के साथ वैश्विक संवृद्धि में पहले स्थान पर है। इस संदर्भ में, जापान और भारत स्वाभाविक साझेदार बने हुए हैं। हमारे गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने हमारे साझा लोकाचार और संस्कृतियों को प्रेरित किया है। हम जापानी “आर्थिक चमत्कार” को एक सीख के अवसर के रूप में देखते हैं क्योंकि हम भारत के संवृद्धि पथ को ऊपर उठाने के लिए आधार तैयार कर रहे हैं। जापान ने कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।²

¹ भारत एक श्रेष्ठ जनसांख्यिकीय लाभांश से संपन्न है। नवीनतम विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) के अनुमान के अनुसार 1.429 बिलियन की कुल आबादी का 68 प्रतिशत 15-64 वर्ष आयु वर्ग का है।

² जापानी सहयोग के माध्यम से पूरी/चल रही कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रसिद्ध दिल्ली मेट्रो शामिल है; वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) और दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी); और मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएचएसआर) भी शामिल है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, रेअर-अर्थ निष्कर्षण, अर्धचालक और समुत्थानशील आपूर्ति शृंखला तथा ऐसी अन्य अग्रणी प्रौद्योगिकियों में सहयोग के कई अवसर हैं। मानव संसाधन के क्षेत्र में भी हमारी साझेदारी संभावित रूप से मजबूत हो सकती है। मुझे विश्वास है कि हमारे लोगों और पूरी दुनिया के लाभ के लिए हमारे संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की भविष्य में असीम संभावनाएं हैं।

यहां भारत के संवृद्धिचालकों, महामारी के बाद से मुद्रास्फीति के प्रबंधन के हमारे अनुभव और विशेष रूप से फिनटेक क्षेत्र में उभरते अवसरों और चुनौतियों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करना सार्थक होगा।

संवृद्धि के चालक

समष्टि-आर्थिक मूल तत्वों को मजबूत करने के लिए नीतिगत प्राथमिकता दिए जाने और निरंतर संरचनात्मक सुधारों ने भारत को संवृद्धि परिणामों के मामले में विशिष्ट बनाया है। यह महामारी के बाद जीडीपी वृद्धि में 2020-21 (महामारी वर्ष) में 5.8 प्रतिशत के संकुचन से 2021-22 में 9.1 प्रतिशत और 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि से परिलक्षित होता है। 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक इशारा करते हैं कि यह गति जारी रहेगी। पूरे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिज़र्व बैंक ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की सहज समुत्थानशीलता का आधार है इसकी बेहतर वैविध्यपूर्ण आर्थिक संरचना। यद्यपि भारत ने व्यापार और वित्तीय चैनलों के माध्यम से बाहरी खुलेपन में तेजी से प्रगति की है और प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता हासिल की है, लेकिन संवृद्धि के लिए इसकी मुख्य निर्भरता घरेलू मांग पर बनी हुई है जो बाहरी आघातों से निपटने के लिए एक सहारा भी प्रदान करती है। सकल मांग के घटकों में निजी खपत का हिस्सा जीडीपी के आधे से अधिक (2011-12 से 2022-23 के दौरान लगभग 57.0 प्रतिशत औसत हिस्सेदारी) है, इसके बाद निश्चित निवेश और सरकारी खपत का क्रम आता है। महामारी के बाद की बहाली के दौरान, निजी खपत ने 2021-22 और 2022-23 के दौरान जीडीपी वृद्धि में औसतन 66.0

प्रतिशत का योगदान दिया³ साथ ही, बैंकिंग, डिजिटलीकरण, कराधान, विनिर्माण आदि से संबंधित संरचनात्मक सुधारों ने मध्यम और दीर्घकालिक अवधि में एक मजबूत और टिकाऊ संवृद्धि की नींव रखी है।

आपूर्ति पक्ष देखें तो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र को नए सिरे से गति देते हुए, अपनी अंतर्निहित गति बनाए हुए हैं, जबकि भारत की संवृद्धि में एक बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है और यह क्षेत्र भी काफी हद तक घरेलू मांग पर निर्भर करता है। भारत के सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और अपेक्षा की जाती है कि अर्थव्यवस्था में हो रहे तेजी से डिजिटलीकरण के लाभ से उसका भविष्य का संवृद्धि मार्ग बेहतर बनेगा, जो आर्थिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भारत की सेवाओं की बाहरी मांग भी तेजी से महत्व प्राप्त कर रही है क्योंकि विशिष्ट क्षेत्रों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण सेवाओं का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। भारत के सेवा निर्यात में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित सेवाओं के अलावा व्यवसाय विकास, अनुसंधान और विकास, पेशेवर प्रबंधन, लेखा और कानूनी सेवाओं जैसी अन्य विविध पेशेवर सेवाएं भी शामिल हो रही हैं। घरेलू सेवाएं भी कम कौशल वाली उपभोक्ता-उन्मुख सेवाओं से अधिक प्रौद्योगिकी-सक्षम व्यावसायिक सेवाओं की ओर लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। नए उभरते स्टार्ट-अप काफी हद तक सेवा क्षेत्र में केंद्रित हैं। भारत के प्रभावशाली सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे⁴ का लाभ उठाते हुए इनमें से कई स्टार्ट-अप डिजिटलीकरण की सुविधा से लेकर क्रेडिट तक पहुंच में सुधार सेवाओं की पेशकश करके अन्य व्यवसायों के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

मुद्रास्फीति का प्रबंधन

जैसा कि संवृद्धि के मामले हैं, अन्य देशों की तुलना में मुद्रास्फीति प्रबंधन के मामले में भारत का अनुभव कुछ अलग है। भारत में 2020 और 2021 के दौरान लगे मुद्रास्फीतिक आघातों

की प्रकृति काफी हद तक आपूर्ति पक्ष से संबंधित थी, जो कोविड-19 लॉकडाउन और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण थे। जैसे-जैसे लॉकडाउन हटाए गए और मौसम का प्रतिकूल प्रभाव कम होने लगा, मुद्रास्फीतिक सुधारों ने जोर पकड़ा। महामारी के दौरान प्रदान की गई मौद्रिक और राजकोषीय सहायता सुविचारित और लक्षित थी। परिणामतः, भारत में मांग-आधारित मुद्रास्फीतिक दबाव कई अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत कम था। इसलिए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के उद्देश्य से बीच-बीच में उच्च मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर गौर कर पाई। एमपीसी ने यह विचार किया कि ऐसे परिदृश्य में नीतिगत सख्ती से संवृद्धि में नरमी बढ़ेगी और आपूर्ति पक्ष के अस्थायी आघातों के पहले दौर के प्रभावों का उचित तरीके से समाधान नहीं हो पाएगा। यह दृष्टिकोण हमारे लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे में निहित लचीलेपन के अनुरूप था, जिसमें मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

2022 की शुरुआत में मुद्रास्फीति पर कोविड-19 के आघातों में कमी आने, आपूर्ति बाधाओं के धीरे-धीरे कम होने और सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के चलते 2022-23 की तीसरी तिमाही तक मुद्रास्फीति में 4 प्रतिशत की लक्ष्य दर के आसपास उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद थी। यूक्रेन युद्ध से स्थिति उम्मीदों के विपरीत हो गई। प्रारंभ में, आघात ईंधन और खाद्य कीमतों में वैश्विक वृद्धि से हुए, जो स्थानीय प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से और बढ़ गए। इन आघातों का असर वस्तु और सेवाओं की खुदरा कीमतों पर पड़ा, क्योंकि घरेलू आर्थिक सुधार और बढ़ती मांग ने दबी हुई बड़ी इनपुट लागतों को अंतरित होने का रास्ता दिया। इससे अंतर्निहित मुख्य मुद्रास्फीति में भी जड़ता आयी। परिणामस्वरूप एक सामान्यीकृत मुद्रास्फीतिक स्थिति बनी।

2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद, भारत में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए जो उल्लेखनीय कार्य हुआ वह था समन्वित मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत प्रतिक्रिया। एमपीसी

³ अन्य तुलनीय बड़े उभरते बाजारों (ईएम) में, संवृद्धि में निजी खपत का योगदान कम था, उदाहरण के लिए 2021 के दौरान चीन में 60.0 प्रतिशत, ब्राजील में 40.0 प्रतिशत और इंडोनेशिया में 31.0 प्रतिशत।

⁴ स्टैकिंग अप दी बेनेफिट्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी, आईएमएफ वर्किंग पेपर, मार्च 2023।

ने संवृद्धि के बजाय मुद्रास्फीति को प्राथमिकता देते हुए तेजी से अपना रुख बदल बदला और अप्रैल 2022 में समायोजन वापस लेने के लिए अपने उदार रुख को वापस लिया। इसके बाद एमपीसी ने मई 2022 और फरवरी 2023 के बीच नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 250 बीपीएस की वृद्धि की, ताकि मुद्रास्फीति की उम्मीदों को सीमा के भीतर रखा जा सके, मुख्य मुद्रास्फीतिक जड़ता से निकला जा सके और दूसरे दौर के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके।

पीछे मुड़कर देखें तो हमारी नीतियों के संचालन के ऐसे कई पहलू थे जिन्होंने 2022-23 में उच्च मुद्रास्फीतिक दबाव के दौरान निर्णायक और समय पर कार्रवाई करने में मदद की। कोविड-19 आघात से निपटने के लिए मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया का पहला आधार था 'विवेकशीलता'। चलनिधि उपलब्ध कराए जाने के अधिकांश असाधारण उपायों को पूर्व-निर्धारित समाप्ति तिथियों के साथ लक्षित किया गया था। संवृद्धि पूर्ववत होने पर इस मौद्रिक प्रोत्साहन को क्रमिक रूप से वापस लेना इससे आसान हुआ। दूसरा, सरकार ने राजकोषीय विवेक का भी पालन किया और 2022-23 के लिए वास्तविक राजकोषीय घाटे को बजट अनुमानों के अनुरूप रखा। तीसरा, मौद्रिक नीति उपायों के पूरक के रूप में सरकार द्वारा सक्रिय और लक्षित आपूर्ति पक्ष के कई उपाय किए गए⁵ ये सभी कारक मूल्य दबावों को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हुए।

वर्तमान परिस्थितियों में एमपीसी ने अक्टूबर 2023 की बैठक में 2023-24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो 2022-23 के 6.7 प्रतिशत से कम है। तथापि, हेडलाइन मुद्रास्फीति खाद्य मूल्यों पर बार-बार होने वाले और अतिव्यापी आघातों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। कोर मुद्रास्फीति में जनवरी 2023 के हालिया उच्चांक के बाद 170 आधार अंकों की कमी आई है। इन परिस्थितियों में मौद्रिक नीति संवृद्धि का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति को

क्रमबद्ध ढंग से लक्ष्य के अनुरूप संरेखित करने के लिए सतर्क और सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी बनी हुई है।

फिनटेक क्षेत्र

फिनटेक के आगमन ने पारंपरिक वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को बदल दिया है। इसने वित्तीय सेवाओं को तेज, सस्ता, कुशल और अधिक सुलभ बनाकर उनके वितरण में काफी सुधार किया है। भारत वर्तमान में भारत में काम कर रहे फिनटेक की संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक पारितंत्र है। यह क्षेत्र मजबूत गति से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक राजस्व में लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है, जो 2030 में वैश्विक फिनटेक उद्योग के कुल राजस्व का लगभग 13 प्रतिशत होगा⁶ डिजिटलीकरण के भारतीय 'मॉडल' की उल्लेखनीय विशेषता उसके बुनियादी ढांचे के निर्माण में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की फिनटेक फर्मों और स्टार्ट-अप द्वारा अभिनव उत्पाद बनाए जा रहे हैं।⁷ जेएएम ट्रिनिटी – जो बैंक खातों (जनधन), आधार, भारत की बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, जो पहचान का एकल और पोर्टेबल प्रमाण प्रदान करती है; और मोबाइल फोन नंबर का एक संयोजन है, ने वित्तीय समावेशन, वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण और समग्र सेवा वितरण के मामले में भारत के फिनटेक पारितंत्र में क्रांति ला दी है।

उल्लेखनीय है कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत में फिनटेक प्रगति में एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। इसकी सफलता की कहानी वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बन गई है। मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच तुरंत धन अंतरित करने की इसकी क्षमता ने लोगों के डिजिटल लेनदेन करने के तरीके को बदल दिया है। बैंकों और भुगतान प्रणालियों के बीच यूपीआई की अंतरपरिचालनीयता से एक एकीकृत भुगतान पारितंत्र स्थापित हुआ है। इसने छोटे व्यवसायों

⁶ https://www.ey.com/en_in/financial-services/how-is-the-fintech-sector-in-india-poised-for-exponential-growth

⁷ 24x7 डिजिटल भुगतान प्रणालियों द्वारा संचालित भुगतान बैंक (2014), डिजिटल इंडिया (2015), स्टार्टअप इंडिया (2016), इंडिया स्टैक, अकाउंट एग्रीगेटर्स (2016), पीयर टू पीयर (पी 2 पी) लेंडिंग प्लेटफॉर्म (2017) जैसी पहलें देश में फिनटेक पारितंत्र के विकास और वित्तीय बाजारों के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए प्रमुख समर्थक के रूप में उभरी हैं।

⁵ इनमें गेहूँ, चावल और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध; पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती; दालों के आयात को आयात शुल्क से छूट; राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को छूट पर दाल उपलब्ध कराना; गेहूँ और दालों के लिए स्टॉक सीमा; विभिन्न खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती और प्रमुख सब्जियों की अतिरिक्त खरीद और रियायती बिक्री आदि शामिल थे।

और सड़क विक्रेताओं के लिए भी डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की है, जिससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है। यूपीआई ने भुगतान से संबंधित नए उत्पादों और सेवाओं के विकास को भी बढ़ावा दिया है⁸ इसके अलावा, यूपीआई को अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने का काम भी शुरू किया जा रहा है। फिनटेक की शक्ति का लाभ उठाने और सीमापार भुगतान को अधिक कुशल और कम खर्चीला बनाने के लिए भारत और जापान की तीव्र भुगतान प्रणाली के बीच संबंध स्थापित करने की संभावना का पता लगाया जा सकता है⁹

रिज़र्व बैंक ने थोक और खुदरा, दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट उपयोग के मामलों के लिए भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी), अर्थात् ई-रुपया का प्रायोगिक उपयोग भी शुरू किया है। फिनटेक पारितंत्र के संबंध में हमारा दृष्टिकोण ग्राहक-केंद्रित होना; सुशासन पर ध्यान केंद्रित करना; प्रभावी निरीक्षण, नैतिक आचरण और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना; और स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के माध्यम से फिनटेक द्वारा स्व-विनियामक को प्रोत्साहित करना है।

यद्यपि वित्तीय नवाचार भुगतान में आसानी को बढ़ाता है और इसकी लागत को कम करता है, वे वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम और चुनौतियां भी पैदा करते हैं। इन जोखिमों का समग्र वित्तीय स्थिरता और बाजार की अखंडता पर असर पड़ता है। इसलिए, हम नवाचार के प्रोत्साहनकर्ता के साथ-साथ विनियामक के रूप में कार्य करने की दोहरी भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं। नवाचार को बढ़ावा देते हुए, हमारा ध्यान एक ऐसा सुविनियमित

पारितंत्र सुनिश्चित करने पर है जो प्रणालीगत जोखिमों और चुनौतियों को विचार में लेता हो।

संक्षेप में

यह संतोष का विषय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों के अस्थिर समय में से सुचारु रूप से गुजरी है। संवृद्धि अपनी अंतर्निहित गतिशीलता से प्रेरित है और एक विवेकपूर्ण नीतिगत प्रयासों के समर्थन से मजबूत होती जा रही है। मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में आ रही है। महामारी के बाद के हमारे आर्थिक कार्यनिष्पादन का श्रेय अत्यंत सुविचारित, केंद्रित और लक्षित मौद्रिक और राजकोषीय प्रयासों को भी जाता है।

साथ ही मुझे यह भी जोड़ना है कि वर्तमान के अनिश्चित वातावरण में, आत्मसंतोष की किसी भी भावना से बचना सबसे अच्छा होगा। हम सक्रिय बने हुए हैं और अपने समष्टि आर्थिक ढांचों और बचाव उपायों को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं। आज, भारत की संभावनाओं में विश्वास और भरोसा अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए, भारत जापान को एक करीबी साझेदार के रूप में देखता है ताकि हम दोनों देशों के लिए संवृद्धि और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत कर सकें। भारत में कुछ ही दिनों में हम रोशनी का त्योहार, दीपावली मनाने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जापान, उगते सूरज का देश, हमारे करीबी साझेदार के रूप में, हमारी अर्थव्यवस्थाओं और हमारे लोगों की भलाई को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे साहस को बढ़ाएगा।

धन्यवाद और नमस्कार।

⁸ हम यूपीआई के नए उपयोग के मामलों पर लगातार काम कर रहे हैं जैसे कि यूपीआई लाइट जो ऑफलाइन भुगतान के लिए पेश किया गया है, और यूपीआई123पे जो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई लेनदेन करने की सुविधा देता है। आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पूरे वर्ष 24x7 आधार पर उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई-पेनाउ लिंकेज फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। कई देशों के साथ इसी तरह के अन्य संबंधों पर काम चल रहा है।

⁹ वर्तमान में, जापान से प्रेषण भारत द्वारा कुल आवक प्रेषण प्राप्ति का केवल एक छोटा सा अंश (0.2 प्रतिशत) है। हालांकि, बैंकों के माध्यम से जापान से भारत में प्रेषण भेजने की लागत संयुक्त राष्ट्र शाश्वत विकास लक्ष्यों (यून-एसडीजी) के 3 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत अधिक है। ये अनुमान विश्व बैंक के रेमिटेंस प्राइस वर्ल्डवाइड डेटाबेस पर आधारित हैं।